राष्ट्रीय पोषण मिशन की स्थापना को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9046.17 करोड़ रुपये के तीन वर्ष के बजट के साथ 2017–18 से शुरू होने वाले राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम) की स्थापना को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। छह वर्ष से कम आयु के बच्चों और महिलाओं के बीच कुपोषण के मामलों से निपटने के लिए सरकार ने कई स्कीमें लागू की हैं। इन योजनाओं के बावजूद देश में कुपोषण तथा संबंधित समस्याओं का स्तर ऊंचा है। योजनाओं की कोई कमी नहीं है किंतु कुपोषण से मुक्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने में विभिन्न योजनाओं के बीच तालमेल में कमी देखने में आई है। एनएनएम सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित करके वांछित तालमेल को कायम करेगा। एनएनएम एक शीर्षस्थ निकाय के रूप में मंत्रालयों के पोषण संबंधी हस्तक्षेपों की निगरानी, पर्यवेक्षण, लक्ष्य निर्धारित करने तथा मार्गदर्शन का काम करेगा।

प्रस्ताव में निम्नलिखित सम्मिलित हैं–

- कुपोषण का समाधान करने हेतु विभिन्न योग्यताओं के योगदान का प्रतिचित्रण।
- योजनाओं में तालमेल हेतु सुदृढ़ तंत्र।
- आईसीटी आधारित लगातार निगरानी प्रणाली।
- लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना।
- आईटी–आधारित उपकरणों के प्रयोग के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा रजिस्टरों के प्रयोग को समाप्त करना।
- आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों की लंबाई का मापन प्रारंभ करना।
- सामाजिक लेखा मूल्यांकन।
- पोषण पर जन आंदोलन के जरिए लोगों की भागीदारी बढ़ाना, पोषण संसाधन केंद्रों की स्थापना करना इत्यादि शामिल है।

मुख्य प्रभाव

यह कार्यक्रम लक्ष्यों के माध्यम से लंबाई में वृद्धि न होने, अल्प–पोषाहार, रक्त की कमी तथा जन्म के समय बच्चे का वजन कम होने के स्तर में कमी के उपाय करेगा। इससे बेहतर निगरानी समय पर कार्यवाही के लिए सावधानी जारी करने में तालमेल बिठाने तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मंत्रालय और राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को कार्य करने, मार्गदर्शन एवं निगरानी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

लाभ एवं कवरेज

इस कार्यक्रम से 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचेगा। सभी राज्यों और जिलों को चरणबद्ध रूप से अर्थात 2017–18 में 315 जिले, वर्ष 2018–19 में 235 जिले तथा 2019–20 में शेष जिलों को शामिल किया जाएगा।

वित्तीय परिव्यय

राष्ट्रीय पोषण मिशन हेतु वर्ष 2017–18 से प्रारंभ तीन वर्षों के लिए 9046.17 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसका सरकारी बजटीय समर्थन (50 प्रतिशत) तथा आईबीआरडी अथवा अन्य एमडीबी द्वारा 50 प्रतिशत वित्तपोषण होगा। केंद्र तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 60:40 पूर्वोत्तर क्षेत्रों तथा हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100 प्रतिशत सरकारी बजटीय समर्थन होगा। तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत सरकार का कुल अंश 2849.54 करोड़ रुपये होगा।

कार्यान्वयन रणनीति एवं लक्ष्य

राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य ठिगनापन, अल्पपोषण, रक्ताल्पता (छोटे बच्चों, महिलाओं एवं किशोरियों में) को कम करना तथा प्रति वर्ष अल्पवजनी बच्चों में क्रमशः 2 प्रतिशत, 2 प्रतिशत, 3 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत की कमी लाना है। हालांकि लंबाई में वृद्धि न होने को कम करने का लक्ष्य 2 प्रतिशत है।